

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4195  
29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

**इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन**

**4195. श्री धर्मवीर सिंह:**

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना आरम्भ कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है;
- (ग) क्या हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूंह जिलों में भी विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और संख्या क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ.) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों का मूल्य कम करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

**(क) से (घ):** महोदय, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है। साथ ही, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं। फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों का हरियाणा सहित राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी थी जिसकी सूची अनुलग्नक-II पर है। 01 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-I और II के अंतर्गत कुल 491 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार देश में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) में कुल 1536 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं जिनकी सूची अनुलग्नक-III में है।

(ड): महोदय, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. दिनांक 11 जून, 2021 से ई-दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी वाहन की लागत को 20% से बढ़ाकर 40% तक कर राशि को 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु दिनांक 12 मई, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। इस स्कीम को कुल 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

फेम इंडिया योजना का चरण-II: भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत किया है। 01 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 18 चार्जिंग स्टेशन (चेन्नई शहर में 7, दिल्ली में 5, नागपुर में 4 और अहमदाबाद में 2) स्थापित किए जा चुके हैं।

राज्य	स्वीकृत ईवी चार्जिंग की संख्या
महाराष्ट्र	317
आंध्र प्रदेश	266
तमिल नाडु	281
गुजरात	278
उत्तर प्रदेश	207
राजस्थान	205
कर्नाटक	172
मध्य प्रदेश	235
पश्चिम बंगाल	141
तेलंगाना	138
केरल	211
दिल्ली	72
चंडीगढ़	70
हरियाणा	50
मेघालय	40
बिहार	37
सिक्किम	29
जम्मू और कश्मीर	25
छत्तीसगढ़	25
असम	20
ओडिशा	18
उत्तराखंड	10
पुडुचेरी	10
अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर)	10
हिमाचल प्रदेश	10
कुल	<b>2877</b>

➤ भारी उद्योग मंत्रालय ने 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत किया है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	एक्सप्रेस वे	स्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन
1	मुंबई-पुणे	10
2	अहमदाबाद-वडोदरा	10
3	दिल्ली-आगरा-यमुना	20
4	बेंगलुरु-मैसूर	14
5	बेंगलुरु-चेन्नई	30
6	सूरत-मुंबई	30
7	आगरा-लखनऊ	40
8	ईस्टर्न पेरिफेरल (ए)	14
9	हैदराबाद ओआरआर	16
क्र. सं.	राजमार्ग	स्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन
1	दिल्ली-श्रीनगर	80
2	दिल्ली-कोलकाता	160
3	आगरा-नागपुर	80
4	मेरठ से गंगोत्री धाम	44
5	मुंबई-दिल्ली	124
6	मुंबई-पणजी	60
7	मुंबई-नागपुर	70
8	मुंबई-बेंगलुरु	100
9	कोलकाता-भुवनेश्वर	44
10	कोलकाता-नागपुर	120
11	कोलकाता-गंगटोक	76
12	चेन्नई-भुवनेश्वर	120
13	चेन्नई-त्रिवेंद्रम	74
14	चेन्नई-बेल्लारी	62
15	चेन्नई-नागपुर	114
16	मंगलदाई-वाकरो	64
		<b>1576</b>

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-II**

फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 520 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है जिनमें से 01.03.2022 की स्थिति के अनुसार 473 चार्जिंग स्टेशन निम्नानुसार स्थापित किए जा चुके हैं:

शहर	चार्जिंग स्टेशन	राजमार्ग	चार्जिंग स्टेशन
चंडीगढ़	48	दिल्ली-चंडीगढ़	24
दिल्ली	94	मुंबई-पुणे	16
जयपुर	49	दिल्ली-जयपुर-आगरा	31
बंगलुरु	60	जयपुर-दिल्ली राजमार्ग	9
रांची	30		
लखनऊ	1		
गोवा	30		
हैदराबाद	57		
आगरा	15		
शिमला	9		
<b>कुल</b>	<b>393</b>		<b>80</b>

01.01.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग सुविधा वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या जहां ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है
आंध्र प्रदेश	65
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	19
बिहार	26
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	51
दिल्ली	66
गोवा	17
गुजरात	87
हरियाणा	114
हिमाचल प्रदेश	13
झारखंड	22
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	100
केरल	39
लेह	2
मध्य प्रदेश	167
महाराष्ट्र	88
मणिपुर	1
मेघालय	3
नागालैंड	2
ओडिशा	26
पुडुचेरी	2
पंजाब	41
राजस्थान	174
तमिलनाडु	76
तेलंगाना	112
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	128
उत्तराखंड	10
पश्चिम बंगाल	71
<b>सकल योग</b>	<b>1536</b>